

संक्षिप्त समाचार

केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी

तिरुवनंतपुरम। प्रवर्तन निदेशालय ने सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस मामले में कुल मिलाकर, एसआईटी ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग इस वक्त ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। ईडी की यह तलाशी ऐसे समय में हो रही है जब केरल हाई कोर्ट की देखरेख में काम कर रही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) मंदिर से सोने की कथित हेराफेरी की समानांतर आपराधिक जांच जारी रखे हुए है। ईडी ने मुख्य आरोपियों के घरों पर तलाशी शुरू की, जिनमें पहले आरोपी उन्नीकुष्णन पोद्दी, सीपीआई(एम) नेता मुरारी बाबू, ए पंचकुमार और एन वासु शामिल हैं।

आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने इस देश से मांगी मदद

नई दिल्ली। पोलैंड के उपप्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोर्सकी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत के सामने सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों पर जोर दिया। उन्होंने पोलैंड से आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाने और भारत के पड़ोस में आतंकवादी ढाँचे को बढ़ावा देने में मदद न करने की अपील की। मीटिंग के दौरान अपनी शुरुआती बातचीत में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और पोलैंड के बीच रिश्ते लगातार आगे बढ़े हैं, हालाँकि लगातार ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, उपप्रधानमंत्री आप हमारे इलाके के लिए अनजान नहीं हैं और क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग में इस इलाके की आपकी हाल की कुछ यात्राओं पर चर्चा होगी। पोलैंड को आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए और हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए।

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में एक जवान शहीद

जम्मू । जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ ने गंभीर रूप ले लिया है। सिंहपोरा इलाके में भीषण गोलीबारी में देश ने अपना एक वीर जवान खो दिया, जबकि सात अन्य जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस शहदत के बाद सुरक्षाबलों ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को चारों तरफ से घेर रखा है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को चतुर बेल्ट के मंदराल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। इलाके की भौगोलिक स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है।

केन्द्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

2031 तक के लिए बढ़ी अटल पेंशन योजना की समयसीमा....

नई दिल्ली/ एजेंसी

आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने बुधवार को दो बड़े और दूरगामी फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जहां एक ओर आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ‘अटल पेंशन योजना’ (एपीवाई) को 2030-31 तक विस्तार दिया गया है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन और लघु उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी दी गई है। ये फैसले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करने और छोटे उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कैबिनेट ने सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस विस्तार के साथ ही योजना के प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और ‘गैप फंडिंग’ के लिए वित्तीय सहायता को भी स्वीकृति मिली है। योजना का दायरा: 9 मई 2015 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आय की सुरक्षा प्रदान करना है। सफलता के आंकड़े: 19 जनवरी 2026 तक इस योजना के तहत 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। पेंशन लाभ: इस योजना के तहत, अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलती है। जागरूकता पर जोर: सरकार विकासात्मक गतिविधियों के जरिए असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता और क्षमता निर्माण का विस्तार करेगी। सिडबी में 5,000 करोड़ की पूंजी: एमएसएमई के लिए ब्रुस्टर डोज- लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को राहत देते हुए सरकार ने सिडबी को 5,000 करोड़ रुपये की इकट्टी सहायता देने का फैसला किया है। यह पूंजी वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस की ओर से



इसके अलावा एमएसएमई के लिए बड़ा फैसला लिया

इसके अलावा, कैबिनेट ने एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इकट्टी सहायता देने को भी मंजूरी दी है। यह राशि वित्तीय सेवा विभाग के जरिए तीन चरणों में दी जाएगी- वित्त वर्ष 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपए, जबकि 2026-27 और 2027-28 में 1,000-1,000 करोड़ रुपए। इस पूंजी से सिडबी अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकेगा और एमएसएमई को ज्यादा मात्रा में सस्ता कर्ज उपलब्ध करा पाएगा। सरकार के मुताबिक, इस इकट्टी निवेश के बाद सिडबी की मदद से वित्तीय सहायता पाने वाले एमएसएमई की संख्या 76.26 लाख से बढ़कर 1.02 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी करीब 25.74 लाख नए एमएसएमई को सीधा फायदा मिलेगा।

1 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होने का अनुमान

मौजूदा आंकड़ों के आधार पर इससे करीब 1.12 करोड़ नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है, क्योंकि औसतन हर एमएसएमई करीब 4 लोगों को रोजगार देता है। सरकार ने बताया कि आने वाले वर्षों में सिडबी की बैलेंस शीट पर जोखिम भारित परिसंपत्तियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बैंक डिजिटल और बिना गारंटी वाले कर्ज, स्टार्टअप को वेंचर डेट और एमएसएमई को ज्यादा फंडिंग उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है। ऐसे में मजबूत पूंजी आधार जरूरी है, ताकि सिडबी की कैपिटल टू रिस्क वेटेड सेटस रेश्यो (सीआरएआर) मजबूत बनी रहे और उसकी क्रेडिट रेटिंग सुरक्षित रहे। अटल पेंशन योजना के विस्तार से करोड़ों लोगों को बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, तो वहीं सिडबी को दी

इकट्टी निवेश से 1.12 करोड़ रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। लाभार्थियों में वृद्धि: वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक 76.26 लाख एमएसएमई को वित्तीय सहायता मिल रही थी, जिसके वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक बढ़कर 102 लाख होने की उम्मीद है। नए उद्यमी: इस कदम से लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। बुधवार को लिए गए ये फैसले संकेत देते हैं कि सरकार का फोकस सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के दोहरे एजेंडे पर है।

टी20 विश्व कप 2026 आईसीसी बैठक संपन्न

बांग्लादेश को ‘भारत में खेलो या बाहर होने’ का अल्टीमेटम

नई दिल्ली/ एजेंसी

टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत से पहले हुए विवाद के लिए आज हुई आईसीसी बोर्ड की बैठक में बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्हें बहुमत के आधार पर भारत में खेलो या बाहर होने का अल्टीमेटम दिया गया है। ईएसपीएनक्रीकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) से बांग्लादेश सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि अगर बांग्लादेश 2026 टी20 विश्व कप में अपने मैच खेलने के लिए भारत जाने से मना करता रहता है, तो



उसकी जगह टूर्नामेंट में दूसरी टीम को शामिल किया जाएगा। यह फैसला वोटिंग के बाद लिया गया, जिसमें आईसीसी बोर्ड के ज्यादातर सदस्य रिफ्लेसमेंट के पक्ष में थे। बीसीबी को भारत में खेलने के अपने रुख पर आईसीसी को जवाब देने के लिए एक और दिन

का समय दिया गया है। इस विवाद की शुरुआत मुंबई इंडियंस द्वारा बांग्लादेश के स्टार पेसर मुस्तफिज़ुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने के बाद हुई। इसके बाद सुरक्षा और टीम माहौल को लेकर बांग्लादेश में नए स्वर उभरे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत यात्रा पर सुरक्षा आशंका जताते हुए कहा कि टीम को श्रीलंका में खेलना चाहिए। उनकी मांग यह थी कि बांग्लादेश को ग्रुप सी से हटाकर ग्रुप बी में भेजा जाए, क्योंकि ग्रुप बी के मैच श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। मौजूदा शेड्यूल में बांग्लादेश अपने लीग मुकामले कोलकाता और मुंबई में खेलेगा।

बंद मकान से एक ही परिवार के पांच लोगों के शव मिले, शरीर पर थे गोलिएं के निशान

सहारनपुर। सरसावा क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बंद मकान के अंदर एक ही परिवार के पांच लोगों के शव बरामद किए गए। सूचना मिलते ही एसपी देहात पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, मकान अंदर से बंद मिला और सभी शवों पर गोली के निशान पाए गए हैं। मृतकों की पहचान अशोक, उनकी पत्नी अंजिता, मां विद्यावती और दो बेटे कार्तिक व देव के रूप में हुई है। अशोक तहसील में अमीन के पद पर तैनात थे। मौके से तीन तमंचे भी बरामद किए गए हैं।

साय कैबिनेट के बड़े फैसले

नवा रायपुर में राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान और स्टार्टअप हब को मंजूरी

रायपुर/ एजेंसी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आवकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये जाने के लिए श्री को विले पारले कलावनी मंडल (स्कूथरु) को उनके नरसी मांजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-

खण्ड का आबंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की है। एसव्हीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तथा वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित है, जोकि एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पाक्स ऑफ



इंडिया के साथ एमओयू का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पाक्स ऑफ इंडिया के 68 केन्द्र संचालित हैं, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित

शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं में उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा संस्था बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।

गरियाबंद में 9 नवसलियों ने किया आत्मसमर्पण, धमतरी-गरियाबंद से एके-47 सहित हथियार जब्त

रायपुर रेंज में चल रहे नवसल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद जिले में 9 नवसलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद उनकी निशानदेही पर गरियाबंद और धमतरी जिलों के जंगलों से नवसलियों के हथियार गए हथियार डंप भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 19 जनवरी 2026 को गरियाबंद जिले में 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। यह राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। आत्मसमर्पित नवसलियों से मिली जानकारी के आधार पर 20 जनवरी को जिला पुलिस और ई-30 टीम को जंगल क्षेत्र में सर्वे ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया।

बीजेपी अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में नितिन नबीन

केरल चुनाव के लिए विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी....

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी कमान संभालते ही चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने एक्शन मोड में आते हुए केरल, बेंगलुरु और तेलंगाना के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। नितिन नबीन ने मंगलवार को जे.पी. नड्डा की जगह लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन में पीढ़ीगत बदलाव के जरिए अपना प्रभाव विस्तारित



करना चाहती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब बात पार्टी के विषयों की आती है, तो वह एक कार्यकर्ता हैं और नितिन नबीन उनके ‘बॉस’ हैं। पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए

नितिन नबीन ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। केरल में अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को सह-प्रभारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, विनोद तावड़े को चंडीगढ़ के नए मेयर चुनाव की देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता राम माधव को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया और महाराष्ट्र के विधायक संजय उपाध्याय को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

राज ठाकरे और शिंदे आएंगे साथ

कल्याण-डोंबिवली में मेयर पद के लिए नया फार्मूला...

मुंबई। महाराष्ट्र की कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केडीएमसी में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से सियासी तस्वीर बेहद दिलचस्प हो गई है। मौजूदा हालात में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि महानगरपालिका की सत्ता का रख अचानक बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन की संभावना पर गंभीर बातचीत चल रही है। यदि यह गठबंधन अंतिम रूप लेता है, तो केडीएमसी में मेयर शिंदे सेना का बन



सकता है, जिससे बीजेपी और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गूट) सत्ता से बाहर हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो यह उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से शिंदे गूट और एमएनएस के नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है।

अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

अवैध खनन से ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई असंभव कोर्ट

जयपुर/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। इस मुद्दे पर सख्त रुख अतनाते हुए अदालत ने अरावली क्षेत्र में खनन और उससे जुड़े सभी पहलुओं की व्यापक जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि अरावली जैसे



संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी गंभीर खतरा है। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.एच. नटराज ने अदालत को आश्चस्त किया कि राज्य में किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा।

संपादकीय

नववर्ष के प्रारंभ में 83 वर्षीय डॉ. माधव गाडगिल का निधन न केवल भारत के एक उच्च शिक्षित पर्यावरणविद को खोने का बड़ा नुकसान है, बल्कि उनके निधन से हमने देश में जैव विविधता संरक्षण की उम्मीदों को भी काफी हद तक झकझोर दिया है। गाडगिल ऐसे समय में हमें छोड़कर चले गए जब प्रकृति संरक्षण के आंदोलन को नेतृत्व देने की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जो इस समय अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रहा है। वैज्ञानिक सोच वाले एक पर्यावरणविद के रूप में, उन्होंने पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के अपने प्रयास वैश्विक विचारकों और विशेषज्ञों द्वारा खतरों की भविष्यवाणी करने और 1992 में ब्राज़ील के रियो में पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित होने से कई साल पहले ही शुरू कर दिए थे. यह महत्वपूर्ण बात है.

माधव गाडगिल को उनके लंबे और उतार-चढ़ाव भरी यात्रा में किए गए अन्य प्रयासों के साथ-साथ नाजुक पश्चिमी घाटों की रक्षा के प्रयासों के लिए कई शानदार श्रद्धांजलियां अर्पित की गई हैं. मैं यह लेख जैव विविधता संरक्षण के लिए उनके योगदान को उजागर करने के लिए लिख रहा हूं. उन्होंने भविष्य में प्रकृति को होने वाले तीव्र नुकसान को भांपते हुए कानूनी उपाय लाने में मदद की. यह उनका मौलिक कार्य था. यदि जैव विविधता- पक्षी, कीट, उभयचर, मधुमक्खियां, तितलियां, पेड़, झाड़ियां, जल निकाय, घास के मैदान आदि – लुप्त हो जाए तो मानव जाति का अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा. प्राचीन लोग और हमारे पूर्वज इसके महत्व को जानते थे और उन्होंने प्रकृति के साथ उस निर्यता से छेड़छाड़ नहीं की, जैसा कि हम आज

रोजाना देख रहे हैं. वर्ष 1971 में, गाडगिल ने वनों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिस्थितिक क्षेत्र अध्ययन शुरू किया. ‘हरित क्रांति’ के नायक डॉ. एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 में स्थापित भारत के जन-जन तक पहुंचाया है। उनका संदेश ‘बुकें दे, बुके नहीं’ केवल एक प्रतीकात्मक नारा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दृष्टि है-जहाँ उपहार में फूलों के गुलदस्ते की बजाय ज्ञान का उपहार देने की प्रेरणा दी गई है। वे मानते हैं कि सत्साहित्य की शक्ति तोप, ठैंक और परमाणु अस्त्रों से भी अधिक है, क्योंकि हथियार ध्वंस करते हैं जबकि साहित्य मानव-मूल्यों में आस्था पैदा करता है और स्थायी परिवर्तन लाता है। सत्साहित्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है-ऐसा परिवर्तन जो सत्ता

चली आ रही इस धारणा को चुनौती दी कि पक्षियों और पौधों की विविधता एक दूसरे से जुड़ी हुई है. तब तक इसे ‘पारंपरिक मान्यता’ माना जाता था. उन्होंने इसे गलत साबित किया. गाडगिल ने न केवल पौधों, पक्षियों और कीटों की प्रजातियों पर काम किया, बल्कि उन्होंने बाघ जैसे विशालकाय स्तनधारियों का भी अध्ययन किया और बाघ सुरक्षा बल में भी योगदान दिया. हालांकि उनके जिस काम ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह था जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) की अवधारणा. रियो शिखर सम्मेलन में जैव विविधता पर एक सम्मेलन (सीबीडी) का सुत्रपात हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 के रूप में एक कानून संसद ने बनाया. यह दो महान विद्वानों – डॉ. स्वामीनाथन और डॉ. गाडगिल

– का प्रारंभिक और संयुक्त प्रयास था, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी; अधिनियम कुछ वर्षों बाद पारित हुआ. उक्त अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया था कि सभी स्थानीय निकाय, ग्रामीण और शहरी – पंचायतें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं – केवल प्रलेखन के बजाय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) स्थापित करें, जिससे स्थानीय समुदायों को व्यापक आधार पर प्रबंधन गतिविधियां करने का अधिकार मिले. पर्यावासों, स्थानीय प्रजातियों, लोक किस्मों और खेती की जाने वाली प्रजातियों तथा सूक्ष्मजीवों का ऐसा दस्तावेजीकरण भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था. यह कानून आज भी लागू है पर कम ही नगर निकाय इस पर काम कर रहे हैं. पुणे के रहने वाले गाडगिल ने पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हाल ही में वे सब जगह ही रही भीषण तबाही को लेकर चिंतित थे.

पढ़ने की लौ एवं किताबों से नाता अटूट है

दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में एक प्रतीकात्मक उत्सव बन चुका है। इस मेले में विश्वप्रसिद्ध लेखकों का आगमन होता है, साहित्यिक संवाद, विमर्श और चर्चाएं होती हैं। विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेत्स जैसे विश्व साहित्य के स्तंभों से लेकर भारतीय भाषाओं के महान साहित्यकारों तक की रचनाएं यहाँ पाठकों को एक साथ उपलब्ध होती हैं। यह मेला भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच देता है और साथ ही विश्व साहित्य को भारतीय पाठकों से जोड़ता है। पुस्तकों को ‘ज्ञान का बाग’ कहा गया है। जो व्यक्ति पुस्तकों से सच्ची दोस्ती कर लेता है, उसे जीवन भर ज्ञान का संबल मिलता है। कठिन समय में पुस्तकें मित्र की तरह साथ देती हैं, मार्गदर्शन करती हैं और समाधान की दिशा दिखाती हैं।

ललित गर्ग
53वें भारत मंडपम् में 10 से 18 जनवरी 2026 तक नौ दिनों के किताबों के जमाबंडे ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि किताबों से नाता कभी नहीं टूट पायेगा। इस मेले में 35 से अधिक देशों के एक हजार से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। यह भव्य विश्व पुस्तक मेला केवल पुस्तकों की खरीद-फरोख्त का आयोजन नहीं है, बल्कि यह उस जीवंत पुस्तक-संस्कृति का उत्सव है, जिसे अनेक लोग डिजिटल युग में कमजोर मानने लगे थे। एक-एक किलोमीटर लंबी कतारें, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की उत्सुक भागीदारी और पुस्तकों के प्रति बढ़ता आकर्षण इस धारणा को स्वस्थ करता है कि पुस्तकें जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर अपार पाठ्य सामग्री एवं साहित्य उपलब्ध होने के बावजूद पुस्तक मेलों में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? छ्छी हुई पुस्तकें एवं शब्द केवल ज्ञान, जिज्ञासा और मनोरंजन की विशाल दुनिया के दरवाजे नहीं खोलते, वे हमें गंध, स्पर्श, संवेदना, सोच, अनुभूति की प्रेरक, अनुकरणीय एवं रोमांचक दुनिया में भी ले जाते हैं। इस वर्ष के पुस्तक मेले के दृश्य पुस्तक-संस्कृति के प्रति नई आशा, नया विश्वास और नया उत्साह पैदा करते हैं। यह मेला स्पष्ट संकेत देता है कि पढ़ने की प्रवृत्ति केवल जीवित ही नहीं है, बल्कि नए पंखों के साथ उड़ान भर रही है।

पुस्तक मेला वस्तुतः एक विषय उत्सव है-ऐसा उत्सव जो ज्ञान, विचार, कल्पना और संवाद को एक साझा मंच देता है। दुनिया भर में पुस्तकों के दायरें को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने और संस्कृतियों को जोड़ने के लिए यह आयोजन अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत कड़ी तथा पीढ़ियों और सभ्यताओं के बीच

एक सेतु का कार्य करता है। यही कारण है कि यूनेस्को हर वर्ष पुस्तक उद्योग के तीन प्रमुख क्षेत्रों- प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और पुस्तकालयों के अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है, ताकि पुस्तक-संस्कृति की प्रेरणा पूरे वर्ष बनी रहे। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि पुस्तकें



केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक संवाद और मानवीय एकता का भी आधार हैं। किताबें अपने सभी रूपों में- मुद्रित, ई-बुक, ऑडियो हमें सोखने, सोचने और स्वयं को सशक्त बनाने का अवसर देती हैं। वे हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं और दूसरों की दुनिया में झांकने का अवसर देती हैं। इस साल का मेला ‘भारतीय सैन्य इतिहास: वीरता और ज्ञान/75’ थीम पर आधारित है, जो भारत की रक्षा बलों के महत्वपूर्ण पलों, योगदानों और कहानियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ‘थीम मंडप 2026’ दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है। यह मंडप भारत की सैन्य विरासत के 75 वर्षों की ऐतिहासिक और निर्णायक यात्रा को दिखा रहा है, जिसकी जड़ें शौर्य, प्रज्ञा और नैतिक मूल्यों में निहित हैं. इसमें कथाओं,

दृश्यात्मक प्रस्तुतियों और संवाद के माध्यम से 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर 2025 तक भारत की सैन्य यात्रा को रेखांकित करता है। दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में एक प्रतीकात्मक उत्सव बन चुका है। इस मेले में विश्वप्रसिद्ध लेखकों का आगमन होता है,



साहित्यिक संवाद, विमर्श और चर्चाएं होती हैं। विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेत्स जैसे विश्व साहित्य के स्तंभों से लेकर भारतीय भाषाओं के महान साहित्यकारों तक की रचनाएं यहाँ पाठकों को एक साथ उपलब्ध होती हैं। यह मेला भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच देता है और साथ ही विश्व साहित्य को भारतीय पाठकों से जोड़ता है। पुस्तकों को ‘ज्ञान का बाग’ कहा गया है। जो व्यक्ति पुस्तकों से सच्ची दोस्ती कर लेता है, उसे जीवन भर ज्ञान का संबल मिलता है। कठिन समय में पुस्तकें मित्र की तरह साथ देती हैं, मार्गदर्शन करती हैं और समाधान की दिशा दिखाती हैं। पुस्तक का महत्व सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक है। किसी भी युग में, किसी भी तकनीकी आंधी में उसका महत्व कम नहीं हो सकता। इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम

बुद्धिमत्ता जैसी अनेक क्रांतियां आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन पुस्तक-संस्कृति अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता बनाए रखेगी। कारण स्पष्ट है-पुस्तकें केवल सूचना नहीं देतीं, वे चिंतन, मनन और विवेक का विकास करती हैं। तकनीक ने ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति अवश्य की है, लेकिन यह



हर समय संभव नहीं कि किताबों के स्थान पर केवल स्क्रीन से पढ़ा जाए। पुस्तक का स्पर्श, उसकी सुगंध, पन्नों को पलटने का अनुभव और पढ़ते हुए होने वाला एकांत संवाद-ये सभी तत्व पुस्तक को विशिष्ट बनाते हैं। पुस्तकें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, सोचने-समझने का दायरा बढ़ाती हैं और व्यक्ति को आत्मअनुशासन सिखाती हैं। पुस्तकें जाग्रत देवता के समान हैं। उनका अध्ययन, मनन और चिंतन तत्काल लाभ देता है। महात्मा गांधी के जीवन पर गीता, टॉल्स्टॉय और थोरो के विचारों का गहरा प्रभाव था। इसी तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैचारिक निर्माण और वैश्विक छवि के किसी भी युग में, किसी भी तकनीकी आंधी में उसका महत्व कम नहीं हो सकता। इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम

प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ जैसे अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने, लिखने और विचार करने की संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाया है। उनका संदेश ‘बुकें दे, बुके नहीं’ केवल एक प्रतीकात्मक नारा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दृष्टि है-जहाँ उपहार में फूलों के गुलदस्ते की बजाय ज्ञान का उपहार देने की प्रेरणा दी गई है। वे मानते हैं कि सत्साहित्य की शक्ति तोप, ठैंक और परमाणु अस्त्रों से भी अधिक है, क्योंकि हथियार ध्वंस करते हैं जबकि साहित्य मानव-मूल्यों में आस्था पैदा करता है और स्थायी परिवर्तन लाता है। सत्साहित्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है-ऐसा परिवर्तन जो सत्ता



और कानून से अधिक टिकाऊ होता है। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी भारत के परिवर्तन में पुस्तक-संस्कृति और सत्साहित्य की निर्णायक भूमिका को स्वीकारते हैं। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, स्थानीय साहित्य का सम्मान और पठन-संस्कृति को प्रोत्साहन देने की दिशा में ठोस पहलें देखने को मिलती हैं। पुस्तकें चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम साधन हैं। उत्तम विचारों से युक्त पुस्तकों के प्रचार-प्रसार से युवाओं को नई दिशा दी जा सकती है। देश की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जा सकता है और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा

सकता है। पुस्तकें प्रेरणा का भंडार हैं, उन्हें पढ़कर व्यक्ति के भीतर कुछ महान करने की आकांक्षा जागती है। वे कल्पवृक्ष भी हैं और कामधेनु भी, क्योंकि उनकी छाया में मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानता है। आज का इसान घर बदलता है, पहनावा बदलता है, रिश्ते और मित्र बदलता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है क्योंकि उसने पुस्तकरूपी कल्पवृक्ष की छाया छोड़ दी है। पुस्तकें व्यक्ति को बदलने का मार्ग दिखाती हैं-सोच, व्यवहार और दृष्टि को सकारात्मक दिशा देती हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलता, वह अपनी मंजिल नहीं पा सकता। आत्मानुशासन, आत्मचिंतन और आत्मविकास-ये सभी पुस्तक-संस्कृति की देन हैं। इंटरनेट और ई-पुस्तकों की बढ़ती पहुंच के बावजूद छ्छी हुई किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है। वे आज भी प्रासंगिक हैं और रहेंगी। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन- ‘साहित्य वह जादू की छड़ी है, जो पशुओं में, ईट-पत्थरों में और पेड़-पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है’, आज भी उतना ही सार्थक है। निश्चित ही, विश्व पुस्तक मेला की प्रेरणा भारतीय जन-चेतना को झकझोर रही है और उन्हें नए भारत-सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित कर रही है। साररूप में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला पुस्तक-संस्कृति और पढ़ने की प्रवृत्ति को नए पंख देने वाला एक अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक आयोजन है। इसका उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं, सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं। यह मेला केवल पुस्तकों का नहीं, विचारों का, संस्कारों का और भविष्य का मेला है-जहाँ शब्द समाज का निर्माण करते हैं और पन्ने इतिहास की दिशा तय करते हैं।

बचत और खर्च का असंतुलन: नये भारत के लिए बड़ी चुनौती

भारतीय परंपरा में बचत को केवल आर्थिक क्रिया नहीं, बल्कि एक सद्गुण माना गया है। ‘आज की बचत, कल का संबल’ जैसी कहावतें हमारे सामाजिक व्यवहार का हिस्सा रही हैं। गृहस्थ जीवन में संतुलन, संयम और संचय को जीवन-मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया। बच्चों की गुल्लक, अनाज के कोठार, गहनों के रूप में सुरक्षित धन, और त्योहारों पर सीमित व सादगीपूर्ण खर्च-ये सब भारतीय जीवनशैली के अभिन्न अंग थे। संकट के समय भारतीय परिवार किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपनी जमा पूंजी और संसाधनों पर भरोसा करता था। यह आत्मनिर्भरता भारतीय समाज की शक्ति रही है। लेकिन बदलती जीवनशैली और बाजार-प्रेरित संस्कृति ने इस परंपरा को कमजोर किया है। आज ‘जियो अभी’ की मानसिकता, आसान कर्ज, ईएमआई संस्कृति, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया पर दिखावे की प्रतिस्पर्धा ने खर्च को एक प्रकार की पहचान बना दिया है। उपभोग अब आवश्यकता से अधिक आकांक्षा से संचालित होने लगा है।

महामारी के बाद की दुनिया केवल स्वास्थ्य के स्तर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक सोच और व्यवहार में भी एक बड़े संक्रमण से गुजरी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती महंगाई, तकनीक-आधारित बाजार और उपभोक्तावादी संस्कृति के तीव्र प्रसार ने लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति को असाधारण रूप से बढ़ा दिया है। इस बदलाव का सबसे गहरा असर घरेलू बचत पर पड़ा है। भारत सहित अनेक देशों में घरेलू बचत दरें ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक बचत निरंतर घटती जा रही है। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चिंता का विषय भी बनती जा रही है। भारत जैसी उपरती अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत संदेव विकास की रीढ़ रही है। बुनियादी ढांचे से लेकर औद्योगिक निवेश तक, भारत की विकास गाथा में घरेलू बचत की भूमिका निर्णायक रही है। परंतु

आज स्थिति यह है कि विशेषकर युवा पीढ़ी में बचत की दर 10 से 15 प्रतिशत तक सिमट गई है। यह आंकड़ा किसी भी उपरती अर्थव्यवस्था के लिए संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब बचत और खर्च के बीच असंतुलन एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में युवाओं की भूमिका हमेशा निर्णायक माना है और वे बार-बार यह संदेश देते रहे हैं कि बचत केवल व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। उनके अनुसार युवाओं से पहले बचत की संस्कृति उपायों में आत्मनिर्भरता, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का विकास करती है। जन-धन योजना, सूचनायुक्त समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, डिजिटल बचत और निवेश के माध्यमों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि छोटे-छोटे नियमित

निवेश भविष्य की बड़ी आर्थिक शक्ति बनते हैं। मोदी का विचार है कि जब युवा वर्ग आज अनावश्यक खर्च से बचकर बचत और उत्पादक निवेश की ओर अग्रसर होगा, तभी भारत की अर्थव्यवस्था



स्थिर, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगी; क्योंकि आत्मनिर्भर युवा ही सशक्त भारत की सबसे बड़ी पूंजी है।

भारतीय परंपरा में बचत को केवल आर्थिक क्रिया नहीं, बल्कि एक सद्गुण माना गया है। ‘आज की बचत, कल का संबल’ जैसी कहावतें हमारे सामाजिक व्यवहार का हिस्सा रही हैं। गृहस्थ जीवन में



संतुलन, संयम और संचय को जीवन-मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया। बच्चों की गुल्लक, अनाज के कोठार, गहनों के रूप में सुरक्षित धन, और

त्योहारों पर सीमित व सादगीपूर्ण खर्च-ये सब भारतीय जीवनशैली के अभिन्न अंग थे। संकट के समय भारतीय परिवार किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपनी जमा पूंजी और संसाधनों पर भरोसा करता था। यह आत्मनिर्भरता भारतीय समाज की शक्ति रही है। लेकिन बदलती जीवनशैली और बाजार-प्रेरित संस्कृति ने इस परंपरा को कमजोर किया है। आज ‘जियो अभी’ की मानसिकता, आसान कर्ज, ईएमआई संस्कृति, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया पर दिखावे की प्रतिस्पर्धा ने खर्च को एक प्रकार की पहचान बना दिया है। उपभोग अब आवश्यकता से अधिक आकांक्षा से संचालित होने लगा है। अनुभवों, ब्रांड और त्वरित संतुष्टि को प्राथमिकता देने से दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा पीछे छूट रही है। उपभोग और खर्च के बीच असंतुलन बढ़ रहा है, जो देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास का आधार माना जाता है, जहाँ घर-परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 70 प्रतिशत) घरेलू बचत से आता है, जो सोने, स्थायी पूंजी और पीपीएफ जैसी योजनाओं में होता है, लेकिन नई पीढ़ी में ‘खर्च करो’ की सोच बढ़ी है, जिससे बचत की दरें घट रही हैं।

के विपरीत है। भारतीय विचार परंपरा न अति भोग की पक्षधर है, न अति त्याग की। संयम, संतुलन और विवेक का मार्ग ही श्रेष्ठ माना गया है। यही सिद्धांत आर्थिक जीवन में भी लागू होता है। उपभोग आवश्यक है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है, रोजगार सृजन होता है और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। परंतु जब खर्च अनियंत्रित हो जाए और बचत उपेक्षित हो जाए, तब व्यक्ति ही नहीं, समाज और राष्ट्र भी असुरक्षित हो जाते हैं। अनुभवों, ब्रांड और त्वरित संतुष्टि को प्राथमिकता देने से दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा पीछे छूट रही है। भारतीय आर्थिक सोच में बचत को आर्थिक सुरक्षा और विकास का आधार माना जाता है, जहाँ घर-परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 70 प्रतिशत) घरेलू बचत से आता है, जो सोने, स्थायी पूंजी और पीपीएफ जैसी योजनाओं में होता है, लेकिन नई पीढ़ी में ‘खर्च करो’ की सोच बढ़ी है, जिससे बचत की दरें घट रही हैं।

संगीत महाविद्यालय, दुर्ग के छात्र छात्राओं ने किया सिया देवी मंदिर एवं तांडुला जलाशय का भ्रमण

दुर्ग। नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने एक यादगार शैक्षिक यात्रा पूरी की, जिसमें सिया देवी मंदिर (बालोद जिला) और तांडुला जलाशय का भ्रमण शामिल था। यह यात्रा न केवल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की स्थलों से परिचय कराने वाली थी, बल्कि छात्रों के बीच आपसी भाईचारे एवं टीम स्पिरिट को मजबूत करने का भी माध्यम बनी।

प्राचार्य डॉ त्रिशा ठाकुर के मार्गदर्शन में यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यात्रा के सारथी रहे जगदीश बामनिया, यशवंत साहू, वत्सल तिवारी एवं जीवनंदन वर्मा। डॉ निधि वर्मा, भारती जंघेल सरला साहू, तपन नाथ के कुशल प्रबंधन से पूरी यात्रा सुचारुवस्थित, सुरक्षित एवं आनंदपूर्ण रही।

यात्रा का प्रथम पड़ाव था श्री सिया देवी मंदिर, जो बालोद जिले के नरगांव क्षेत्र में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर देवी सीता (सिया देवी) को समर्पित है। स्थानीय लोककथाओं एवं रामायण से जुड़े

इतिहास के अनुसार, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण एवं माता सीता ने दंडकारण्य में इस क्षेत्र में निवास किया था। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल एवं पास ही स्थित प्राकृतिक झरना इसे एक आध्यात्मिक एवं पर्यटन स्थल बनाते हैं। सब ने यहां पूजा-अर्चना की और

मंदिर परिसर में संगीतात्मक प्रस्तुति दी, जिसमें विभिन्न रागों एवं लोक गीतों के माध्यम से भक्ति भाव व्यक्त किया गया। यह प्रस्तुति पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को भी आकर्षित कर पाई।

दोपहर में छात्रों ने तांडुला डैम का भ्रमण किया, जो बालोद जिले में तांडुला एवं सुखा नाला

नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध ब्रिटिश काल में 1910 में निर्माण शुरू होकर 1921 में पूर्ण हुआ था। इसका जलाशय क्षेत्र लगभग 827 वर्ग किमी है तथा कुल भंडारण क्षमता 302-312 मिलियन घन मीटर है। यह दुर्ग-भिलाई क्षेत्र को पेयजल एवं भिलाई इस्पात संयंत्र को औद्योगिक

जल उपलब्ध कराता है। डैम की शांत जलराशि, हरियाली एवं सूर्यास्त का नजारा देख छात्र मंत्रमुग्ध हो गए। यहां भी छात्रों ने संगीत प्रस्तुति दी, जिससे परिसर में एक सांस्कृतिक उत्सव जैसा माहौल बन गया। यात्रा की सबसे खास बात रही। सीनियर एवं जूनियर छात्रों के बीच का आपसी

संबंध और भी गहरा एवं सौहार्दपूर्ण हो गया। सभी ने एक-दूसरे की मदद की, हंसी-मजाक किया और मिलकर यादें सृजित कीं। यह यात्रा केवल ज्ञानार्जन की नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास एवं टीमवर्क की भी मिसाल बनी।

गुंडरदेही में सुबह का नाश्ता एवं शाम की चाय बेहद स्वादिष्ट एवं ताजगी भरी रही। बालोद में मिला लाजवाब खाना एवं वहां का शानदार सत्कार सभी के दिल को छू गया। स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी ने यात्रा को और भी स्मरणीय बना दिया। प्राचार्य डॉ त्रिशा ठाकुर ने कहा, 'ऐसी यात्राएं छात्रों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़ाकर वास्तविक जीवन की सीख देती हैं। संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने न केवल स्थलों का ऐतिहासिक महत्व समझा, बल्कि संगीत के माध्यम से अपनी कला भी प्रस्तुत की। यह यात्रा महाविद्यालय के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण रही और छात्रों के लिए जीवन भर की याद बन गई।

सरकारी अस्पतालों से अब निजी सेंटरों में सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे मरीज, आयुष्मान कार्ड स्वीकार न करने वाले अस्पतालों पर होगी बड़ी कार्यवाही

अम्बिकापुर। सरगुजा संभाग में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने संभाग के सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर (Refer) करना अब बंद करना होगा।

रेफरल की निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य : डॉ. शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि मरीजों को रेफर करने के लिए पहले से ही एक निश्चित श्रृंखला (Chain) निर्धारित है। इसके तहत मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) से जिला अस्पताल और वहां से मेडिकल कॉलेज भेजा जाना चाहिए। आवश्यक सुविधाएं होने के बावजूद मरीजों को निजी संस्थानों में

भेजना नियमों के विरुद्ध है और इस पर रोक लगाई गई है।

अस्पताल परिसर से हटेंगी निजी एम्बुलेंस: आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई शासकीय अस्पतालों के बाहर खड़ी निजी एम्बुलेंस के संचालक मरीजों के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे परिसर में विवाद की स्थिति बनती है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी सरकारी अस्पताल परिसर के भीतर कोई भी

निजी एम्बुलेंस खड़ी न रहे।

आयुष्मान कार्ड से इलाज में आनाकानी करने वाले अस्पतालों पर होगी सख्त कार्यवाही: प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई निजी अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट और आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत होने के बावजूद कार्ड के माध्यम से इलाज करने से परहेज कर रहे हैं। डॉ. शुक्ला ने ऐसे निजी चिकित्सा संस्थानों को चिन्हांकित करने और नर्सिंग होम एक्ट-2013 के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

जिले के अधिकारियों को निर्देश: संभागीय संयुक्त संचालक ने संभाग के अधीनस्थ अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। साथ ही, सभी निजी अस्पतालों की बैठक आयोजित कर उन्हें इन नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

दुर्ग। जिला कांग्रेस कांग्रेस जिलाध्यक्ष धीरज बाकलीवाल विमोचन करते हुए।

दुर्ग /विशेष संवाददाता। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने दुर्ग में एक सादगीपूर्ण समारोह में लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप और एस.आर. हॉस्पिटल एंड कॉलेज द्वारा प्रदान की जा रही उल्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का यह संयुक्त प्रयास समाज के लिए अनुकरणीय है।

ऐसे सहयोग से समाज में जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है।

साराहनीय कार्यों की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा,मीडिया और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के दो मजबूत स्तंभ हैं। लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप की निष्पक्ष पत्रकारिता और एस आर हॉस्पिटल एंड कॉलेज द्वारा प्रदान की जा रही उल्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का यह संयुक्त प्रयास समाज के लिए अनुकरणीय है।

ऐसे सहयोग से समाज में जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है।

कार्यक्रम में दुर्ग शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने दोनों संस्थानों के भविष्य के महात्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। साथ ही, उन्होंने प्रदेशवासियों, लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप और एस आर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के सभी सदस्यों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

चेयरमैन श्री संजय तिवारी ने जिलाध्यक्ष

धीरज बाकलीवाल और दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

यह संयुक्त कैलेंडर न केवल समय प्रबंधन का साधन है, बल्कि समाज सेवा, पत्रकारिता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की साझेदारी का प्रतीक भी है।

छत्तीसगढ़ के विकास और समाज कल्याण के लिए ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहें, यही कामना है।

एस.आर. हॉस्पिटल एंड कॉलेज में क्रिकेट का महासंग्राम नित्या भत्या 11 ने जीता फाइनल मैच, गीता और आदिला खान बनी ‘प्लेयर ऑफ द मैच’



दुर्ग/खेल प्रतिनिधि । एस.आर. हॉस्पिटल एंड कॉलेज द्वारा आयोजित क्रिकेट महासंग्राम के महिला क्रिकेट कप का समापन हो चुका है, जिसमें नित्या भत्या 11 ने रोमांचक फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया।

बुधवार को महिला क्रिकेट कप में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए गोल्डन क्लब और बालाजी 11 के बीच मुकाबला हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए



बालाजी 11 ने 10 ओवरों में 72 रन बनाए। जवाब में, गोल्डन क्लब की टीम दबाव में आ गई और महज 45 रन पर आउट हो गई। इस तरह, बालाजी 11 ने यह मैच जीतकर तीसरा स्थान पक्का किया।

इसके बाद, नित्या भत्या 11 और नित्या 11 के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा। नित्या भत्या 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर

आईसीसीसी के माध्यम से धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी

मुंबेेली। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत आईसीसीसी रायपुर द्वारा सतर्क एप के माध्यम से राइस मिलों में वाहन क्षमता से अधिक धान परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर कलेक्टर कुन्दन कुमार द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संयुक्त जांच दल का गठन किया गया और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त जांच दल द्वारा जिले की कुल 13 राइस मिलों की जांच की गई। जांच के दौरान उपलेटा राइस मिल, हाजी राइस मिल, उपलेटा ट्रेडर्स, हाजी परकोइलिंग, एस.एस. पूह, नेशनल दाल मिल, नवकार दाल उद्योग, वर्धमान राइस मिल, जैन राइस इंडस्ट्रीज, वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज एवं जनता राइस मिल सहित अन्य मिलों में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिसके पश्चात संबंधित सभी 13 राइस मिलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। साथ ही मिलिंग कार्य पर रोक लगाने हेतु संबंधित मिलर्स की मिल आईडी को

ब्लॉक करने एवं शेष उठाव हेतु डी.ओ. निरस्त करने उच्च कार्यालय को पत्र लिखा गया है।कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी में पारदर्शिता जिला प्रशासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। धान खरीदी, भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार आगे भी सतत निगरानी एवं कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आईसीसीसी के माध्यम से धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी - राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मिलर्स द्वारा समितियों से धान उठाव का कार्य किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए शासन द्वारा

आईसीसीसी कमांड सेंटर का गठन किया गया है। इसके तहत धान परिवहन में लगे वाहनों को जीपीएस के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। समिति से धान उठाव के बाद यदि कोई वाहन अधिक समय तक एक ही स्थान पर रुकता है या मार्ग परिवर्तित करता है अथवा निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में धान का परिवहन करता है, तो इसकी सूचना कमांड कंट्रोल पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित होती है, जिसकी जांच जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा की जाती है। अवेध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चैकसी को और मजबूत करते हुए सतत निगरानी रखी जा रही है।

मुंबई क्लाइमेट वीक 2026में यूनिसेफ युवाह की बड़ी भूमिका, बच्चों और युवाओं की आवाज बनेगा मंच

मुंबई। यूनिसेफ ‘युवाह’ को ‘मुंबई क्लाइमेट वीक’ 2026 के लिए युवाओं को जोड़ने वाला आधिकारिक पार्टनर बनाया गया है। यह कार्यक्रम 17 से 19 फरवरी 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया, ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ और ‘युवाह’ के साथ मिलकर, जनवरी महीने से ही कई गतिविधियां शुरू कर देगा। इसका मकसद बच्चों और युवाओं को पर्यावरण बचाने की चर्चाओं और फैसलों में शामिल होने और अपनी राय देने का मौका देना है।

मुंबई क्लाइमेट वीक भारत का पहला ऐसा मंच है जो शहर के लोगों की मदद से पर्यावरण की समस्याओं के समाधान खोजेगा। इसका लक्ष्य जलवायु से जुड़ी बड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना है। यह माना जाता है कि पर्यावरण का संरक्षित बच्चों के अधिकारों से भी जुड़ा है। इसलिए, यूनिसेफ इंडिया, युवाह और प्रोजेक्ट मुंबई मिलकर काम करेंगे ताकि पूरे हफ्ते के दौरान बच्चों और युवाओं के अनुभवों व सुझावों

को सुना जाए और उन पर काम किया जाए। इस अभियान के बारे में बात करते हुए यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंधिया मैककेफ्री ने कहा, “बच्चे और युवा बदलाव लाने की बड़ी ताकत रखते हैं। पर्यावरण को बचाने के समाधानों में बच्चों को सबसे आगे रखकर, हम सरकारों के साथ मिलकर उनके अधिकारों और एक बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ‘मुंबई क्लाइमेट वीक’ युवाओं को ई-वेस्ट जैसी चुनौतियों का हल निकालने के लिए एक मंच देता है। इससे पता चलता है कि आज के युवा पर्यावरण को बचाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।”

मुंबई क्लाइमेट वीक की तैयारी के रूप में, यूनिसेफ ‘युवाह’ 9 से 16 फरवरी 2026 तक मुंबई के कुछ चुनिंदा कॉलेजों में ‘कैंपस क्लाइमेट रोड शो’ आयोजित करेगा। इस रोड शो की मुख्य विशेषता ई-वेस्ट से बनी एक खास प्रदर्शनी (इन्स्टलेशन) होगी। इसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा,



पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से ‘मिशन लाइफ’ के तहत ‘विशेष अभियान 5.0’ के माध्यम से तैयार किया गया है। यह प्रदर्शनी ई-वेस्ट के निपटान और चीजों के जिम्मेदारी से इस्तेमाल को लेकर युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।

कॉलेज परिसरों में प्रदर्शनी लगाकर, रोडशो का उद्देश्य मुंबई क्लाइमेट वीक के

यह 16 से 24 उम्र के बदलाव लाने वाले युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। इस चैलेंज के तहत तीन मुख्य विषयों पर युवाओं से उनके नए विचार आमंत्रित किए गए हैं: खाद्य प्रणाली, शहरों को बेहतर बनाना और ऊर्जा के नए स्रोत। चुने गए युवाओं को मुंबई क्लाइमेट वीक में अपने समाधान प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। साथ ही, वे विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत कर सकेंगे और अपने विचारों को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए जरूरी सहयोग के अवसरों को तलाश सकेंगे।

‘प्रोजेक्ट मुंबई’ के संस्थापक और सीईओ शिशिर जोशी ने कहा, “कैंपस रोड शो और यूथ ग्रीन इन्वोल्वेशन चैलेंज इस बात की मिसाल हैं कि मुंबई क्लाइमेट वीक (MCVW) असल में क्या है—यानी जरूरी चर्चाओं के माध्यम से विचारों को हकीकत में बदलना। इन कार्यक्रमों को कॉलेज के छात्रों तक ले जाकर हम युवा पर्यावरण रक्षकों का एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं, जो

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि 2030 से 2050 के बीच, जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और भीषण गर्मी की वजह से हर साल 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। इनमें बच्चों को सबसे अधिक खतरा है। भारत में लगभग हर तीसरा व्यक्ति 14 साल से कम उम्र का है, इसलिए बच्चों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

इस खतरे और बच्चों पर केंद्रित जलवायु कार्यक्रमों की जरूरत को देखते हुए, ‘बाल अधिकार सम्मेलन’ और इसकी हालिया व्याख्याओं ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन दरअसल बाल अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। ‘मुंबई क्लाइमेट वीक’ जलवायु से जुड़े कामों को इन अधिकारों और एहड्ड#0 की प्राथमिकताओं के साथ जोड़ता है। यह इस बात पर जोर देता है कि जलवायु से जुड़े किसी भी बड़े फैसले में बच्चों के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए।